को मिली है उसको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि क्या जिसको छापा था वह पूर्ण है या नहीं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर दूरदर्शन पर सीरियलाइज करके एक-एक दिन में इसके पूरे पृष्ठों को समाज के सामने रखा जाए।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): जो बात आपने कही है इसमें खासतौर पर हिन्दी के अंदर जो छपी थी हुई है, इसके दो हिस्से हैं एक हिन्दी का और दूसरा अंग्रेजी का। लेकिन केवल अंग्रेजी का औथेंटिक है हिन्दी का नहीं है। अगर किसी कोर्ट में कोई केस जाता है तो हिन्दी संविधान का उल्लेख वहां नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आजादी के 50 साल बाद भी राष्ट्र भाषा हिन्दी के अंदर हम किसी कोर्ट में कोट नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बात गोयल जी ने उठाई है उसके साथ मैं अपने को संबद्ध करता हूं।

RE: SITUATION ARISING OUT OF RECENT EARTHQUAKES AND FLOODS IN HIMACHAL PRADESH

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन और सरकार के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि 29 जुलाई की रात्रि को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूकम्प ने विनाश लीला रची है। इसमें सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और हजारों लोग आज वहां पर प्रभावित हुए हैं। इस भूकम्प से मंडी जिले के सुन्दरनगर शहर, वहां की हरिजन बस्ती, अम्बेडनगर और इसके आस पास की तीन पंचायतें प्रभावित हुई हैं। महोदय, भगवान की कृपा से यह दुर्घटना रात को घटी लेकिन जन-जीवन का कोई नुकसान नहीं हुआ।

लेकिन गैर सरकारी सम्पत्ति को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। मुख्य मंत्री महोदय घटना स्थल पर गये और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जिसका मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको 30 हजार रुपया मिलेगा और जिसका आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको 15 हजार रुपया मिलेगा। यह इतनी कम राशि है कि इसमें कोई भी मकान नहीं बना सकता है। एक तो ऊपर से बरसात का मौसम है, लोग बेघर पड़े हुए हैं। हर घर में पानी टपकता है और जैसे ही बारिश ज्यादा हो रही है, वह मकान ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक गिर रहे हैं। गरीब और किसान बैठा रो रहा है। मान्यवर, जैसे तो चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा पड़े, यह सब प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत आते हैं। मैं यह जानता हूं कि इसमें सरकार भी यह कहेगी कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार की तरफ से एक फिक्सड राशि दी गई है, उससे सरकार गुजारा करे। लेकिन आप भी इस बात से सहमत होंगे कि भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसकी न तो कोई पूर्व सूचना होती है और न कोई ऐसा संकेत मिलता है कि इस वर्ष भूकंप आने वाला है। जब भूकंप आता है तो बहुत बड़ी मात्रा में क्षति होती है इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सरकार के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे भूकंप से जो नुकसान होता है, देश के किसी भी भाग में हो, सरकार को चाहिये कि वहां केन्द्रीय दल भेजे और स्पेशल राहत मिलनी चाहिये। फिक्सड राहत राशि से इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है और वहां पर यह भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिये कि जो राहत राशि दी जा रही है, उसमें भी भेदभाव हो रहा है। लोग जगह-जगह सड़कों को बंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। अभी भूतल मंत्री जी यहां से उठ कर चले गये। उनसे संबंधित विषय है। मेरा यह निवेदन है कि उनके ध्यान में बात लाई जाए। हाल ही में जो आर्थिक वर्षा हुई उसमें कुल्लू और चम्बा जिले बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। महोदय, कुल्लू जिले में जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, कुल्लू और मनाली के बीच में चार किलोमीटर सड़क बिलकुल बह गई है और सरकारी तथा गैर सरकारी सम्पत्ति को जो क्षति हुई है, वह लगभग 25 करोड़ रुपये की आंकी गई है। महोदय, जहां तक राष्ट्रीय उच्च मार्गों का संबंध है, उनके रख-रखाव के लिए, निर्माण के लिए सारी धनराशि केन्द्र देता है। जब यह सड़क क्षतिग्रस्त होती है तो यह केन्द्र का दायित्व है कि इसको जल्दी से जल्दी प्रदेश की सरकारों के माध्यम से ठीक करवाए। गतवर्ष भी नुकसान हुआ। मैंने इस माननीय सदन में विषय उठाया केन्द्रीय सरकार ने पैसा दिया लेकिन सड़क की सिर्फ मरम्मत की गई और गाड़ियां चल पड़ी। महोदय, अब व्यास नदी ने अपना रुख बदल लिया है। इसलिए मात्र उस सड़क की मरम्मत स्थाई हल नहीं होगा, अस्थाई हल होगा। जरूरत इस बात की है कि आज उस सड़क का अलाइनमेंट बदला जाए, स्थाई हल ढूंढा जाए। इस सड़क से न केवल कुल्लू प्रभावित होता है बल्कि जब यह टूटती है तो हमारा जो जनजातीय क्षेत्र लाहोल और स्पिति का है,

वह भी प्रभावित होता है। जो मनाली से लेह सड़क जाती है वह बार्डर रोड आर्गेनाइज़ेशन के पास है लेकिन बार्डर रोड आर्गेनाइज़ेशन को पास भी धन का अभाव है। वह सड़क को प्रोपरली मेनटेन नहीं कर पा रहे हैं। जनजातिय क्षेत्र की जो बैमौसम सब्जियां हैं, आज लगभग 70-80 ट्रक मटर से लदे हुए फंसे पड़े हैं, देश की सुरक्षा के लिए यह सड़क आवश्यक है, जितनी भी आर्मी की सप्लाई जाती है उसके लिए यह शार्टेस्ट रूट है। आज वह सड़क अवरुद्ध हो जाने से आर्मी की सप्लाई में बाधा उत्पन्न हुई है। मंत्री महोदय, अब आ गये हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग कुल्लु के लिए और जो बार्डर रोड जाता है मनाली से लेह लद्दाख के लिए उसकी तरफ विशेष ध्यान दें ताकि जल्दी से जल्दी वह ठीक हो सके। न केवल राष्ट्रीय उच्च मार्ग बल्कि जो ग्रामीण सड़कें हैं वह भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। महोदय, हमें उम्मीद थी कि सेंट्रल रोड फंड के बारे में जो एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से दोनों सदनों में वर्षों पहले पारित किया गया, उस पर सरकार कोई न कोई कारगुज़ारी करेगी। मैंने इस पर आधे घंटे की चर्चा भी उठाई थी। उस चर्चा में भाग लेते हुए मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही मंत्रिमंडल की उपसमिति की रिपोर्ट आ जाएगी सेंट्रल रोड फंड में वृद्धि के बारे में जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन खेद का विषय है कि जब मैंने इस बार यह प्रश्न पूछा तो मंत्री महोदय ने स्वयं पहले जवाब दे दिया कि वह उपसमिति अब है ही नहीं, तोड़ दी गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर सेंट्रल रोड्ज़ के बारे में जो प्रस्ताव दोनों सदनों ने सर्वसम्मति पारित कर दिया था, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा, क्योंकि अब तो कोई उपसमिति भी नहीं रही जो कि उसके ऊपर विचार कर रही हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों सदनों द्वारा जो सैन्ट्रल रोड फंड के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ है उसको कार्यान्वित करें ताकि सभी प्रांतों को उनका हिस्सा मिल सके और ऐसी सड़कों को वह मेंटेन कर सकें। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष, महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी भी कुछ कहें, क्योंकि वह कहना चाहते हैं।

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): The hon. Member has asked about the resolution. The Cabinet had taken it up several times. It is being postponed because they say that it is connected with petrol hike. I have not disposed it of. As soon as that is decided, they are going to allocate money for this. That is the promise that has been given to me. That assurance has been given. I am waiting.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (Delhi): Are you going to hike petrol prices?

SHRI T.G. VENKATRAMAN: They say that it is interconnected. The assurance has been given. It is interconnected with the hike. At that point of time, it will be done.

श्री महेश्वर सिंह: महोदय, वह हाइक तो जब होगी तब होगी, लेकिन जब यह सैन्ट्रल रोड फंड तय हुआ था उसके बाद तो अनेकों बार हाइक हो चुकी है। उसके....(व्यवधान) जो सैन्ट्रल रोड फंड में पैसा है उस तो दीजिए।...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष, (श्री सनातन बिसि): मंत्री जी ने वह तो बोल दिया। श्री मलकानी जी

RE. PROPOSAL TO DEMOLISH INDIA GATE CANOPY

SHRI K.R. MALKANI (DELHI): Mr. Vice-Chairman, I rise to raise the issue of the canopy at India Gate. Originally, the statue of King George V used to adorn that canopy. More than 40 years ago, a patriotic young man went to India Gate, he took a ladder with him, waded through water and hammered away the poor nose of King George V. Until then the Government did not have the sense to politely, courteously and with dignity remove that statue. This work was done by a patriotic young man. But to this day the Government has not been able to decide as to what to do with that canopy and whose statue should be put up there.

I am reminded of Indonesia. In front of the Merdeka Palace, the President's Palace in Jakarta, there was a large space and one of the first things that President Sukarno did was to put up a huge statue of Sri Ram with bow and arrow, pulling at the string. More than 90 per cent of